Statement

List of Pojects of aroud Rs 2 crores that are being set up in the joint sector in collaboration with USA

S. No.	Name of the Unit	Item of manufacture	Name of approved collaborator
1.	M/s. Himachal Futuristic Communications Ltd. (A joint sector unit of Himachal Pradesh State Electronic Development Corporation).	Analog Subscriber Carrier Systems	M/s Sciscor Technologies, USA.
2.	M/s. Rajasthan State Industrial Development Corporation Ltd. (Jointly with M/s. IGTEL, Calcutta)	Analog Subscriber Carrier Systems	M/s Ericsson Network Systems, USA.

News Item captioned "Selling Eye for Money"

@2109. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the Delhi Edition of the Indian Express, dated the 15th October, 1988 under the caption "Selling eye for money" wherein it has been stated that a farmer has offered to sell his eye to earn money to feed his family; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE(KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Yes, Sir.

(b) For donating the eye a voluntary pledge has to be signed with a registered eye bank and the eyes are removed in such cases only after death by a trained surgeon.

@Previously Unstarred Question 1082, transferrtd from the 18th November, 1988.

Entry Examination for the I.P.S.

2110. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to delink the entry examination to the Indian Police Service from the existing Combined Civil Services Examinations;

(b) whether Government had introduced similar experiment in some other Police Organisations of the Central Government; and

(c) whether the desired objectives were achieved in such an experiment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) There is no proposal to delink the Indian Police Service from the Civil Services Examination. However, the Union Public Service Commission have appointed, on 12th September, 1988, a Committee of Exoerts to review the Scheme of the Civil Services Examination.

(b) and (c) Recruitment to only one of the Central Police Organisations, viz. the Central Industrial Security Force, is made through the Civil Services Examination. Recruitment to the other Central Police Organisations is made through a Joint Selection Committee.

जन्म दर कम करने के लिये अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता कार्यक्रम

2111. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन्म दर को कम करने तथा बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य को अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता के अधीन उपलब्ध कराई गई मात्रा क्या है तथा संबद्ध जिलों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जिनके नाम उस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और यदि कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है तो उसके कब तक लिये जाने की सम्भावना है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) यू एस एंड सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजन 1980–86 में पांच राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। इस परियोजन से लाभान्वित जिलों और प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त सहायता का एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये) गुजरात सरकार ने सूरत, बानासकांठा और बलसाड जिलों के दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव किया है। गुजरात राज्य को यू एस एड सहायत प्राप्त क्षेत्र परियोजना के बदले विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत लाने का निश्चय किया गया है। समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत 1990 तक 170 लाख अमरीकी डालर की यू एस एड सहायता भी बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए उपलब्ध है जिसे गुजरात के पंचमहल तथा महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के चार-चार खण्डों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

यू एस एड सहायता का राज्यवार विवरण और प्रत्येक राज्य में लाभान्वित जिले

क्रम सं०	राज्य का नाम	लाभान्वित जिला	प्राप्त सहायता की मात्रा
1.	गुजरात	1. भड़ौच 2. पंचमहल	15.76 करोड रुपये
2.	हरियाणा	1. भिवानी 2. सिरस 3. मोहिन्द्र गढ़	8.75 करोड़ रुपये
3.	हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा 2. हमीरपुर 3. सिरमौर	14.75 करोड़ रुपये
4.	महाराष्ट्र	1. उस्मानाबाद 2. परभाणी 3. लातूर	15.13 करोड़ रुपये
5.	पंजाब	1. भटिंडा 2. फरीदकोट 3 संगरूर	12.34 करोड़ रुपये